HRA an USIUN The Gazette of India



असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

t• 638] No. 638] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नर्ट दिल्ली 29 दिसम्बर 1991

का आ 975 (अ) 1 ९क्क/आई डी आर ए/९4 —— भारत मर्ग्यार के उद्योग मृत्रात्रय (अादोगिक विकास विभाग) ने आरेण स 320 (अ)/1 ९क्क/आई डी जार ए/७७ नारीख 26 मई 1979 द्वारा (जिसे इससे इसके पश्चात उना आदेश कहा गत्रा है) मैंसर्भ अपोला जिप्पर बस्पनी प्रान्वेट लिमिनेंच कलकत्ता नामर सम्पण औद्योगित उप कम का प्रवन्ध उद्योग (विकास और तिनियमन) अिर्मियम 1951 (1951 का 65) की धारा 1 ९क्व की उपधारा (1) क खण्ड (क) के अधीन 25 मई 1992 तक की जिसम यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अविध क लिये ग्रहण किया गया था और मिचव तद और रुग्ण उद्योग विकास विभाग पिचमी बगाल सर्वार कि जिसे अव सचिव ओद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग पिचमी बगाल सर्वार कहा जाता है, उक्त ओद्योगिक उपक्रम का प्रवन्ध ग्रहण करन कि तिये प्राधिकृत किया गया था,

और वेन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेण पूर्वीक्त तीन वप की अविष्य की समाप्ति क पण्चात प्रभावी बना रहे, 31 दिसम्बर 1984 तक की, जिसमे यह तारीख भी सम्मिला न और अवधि दे तिये ऐसे जारी रहने के लिये, समय-समय पर, निदेश जारी किये थे (देखिए भारत सरकार के उन्हों समय-समय पर, निदेश जारी किये थे (देखिए भारत सरकार के उन्हों समयालय (औद्यागिक विकास विज्ञाग) के आदेश स का आ 246 (अ)/19क्म/आई की आर ए 92 तारीख 25 मई 1992, का आ 932 (अ)/19क्म/आई की आर ए/92 तारीख 21 नवम्बर 1992, का आ 395 (अ)/19क्म/आई की आर ए/93, तारीख 31 मड 1993 का या 972 (अ)/19क्म/आई की आर ए/93 तारीख 30 नवम्बर 1993 और का आ 272 (अ)/19क्म आड की आर ए/94 तारीख 25 जन 1994)

और देन्दीय सरकार की यह राय हे कि लाइहित में यह समीचीन है कि उस्त आदण ३। मार्च 1955 कि शी, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और जबधि के तिये प्रभावी बना रहे

अत अब कन्द्रीय सरकार उद्योग (तिकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) सी धारा 195 सी उपधारा (2) र परन्तुक के साथ पठित धारा 15क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हण यह निदेल देती है कि उक्त आदेश 31 माच 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मितित है और अवधि क तिये प्रभावी बना रहेगा

[का स 2 (१५) 50 मी / य एस] ए पर सर्वत स्वक्त स्विव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 29th Eccember, 1984

S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84.--Whereas by order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development No. S.O. 320(E)]18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal called Secretary, Industrial Reconstruction Department. Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertakings;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that

the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuation for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 246(E)[18AA]IDRA]82, dated the 25th May, 1982, S.O. 832(E)[18AA]IDRA]82 dt. 24th November, 1982, S.O. 385(E)[18AA]IDRA]83, dated the 31st May, 1983, S.O. 872(E)[18AA]IDRA]83, dated the 30th November, 1983 and S.O. 472(E)[18AA]IERA]84, dated the 28th June, 1984);

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of the 31st March, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the provise to sub-section (2), of section 18A ofthe Industries (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

[File No. 2(23)|80-CUS] A. P. SARWAN, Jt. Secy.